कोरोना काल में छह लाख नई इकाइयां, 23 लाख को रोजगार

एक लाख से अधिक श्रमिकों को छोटे जिलों में ही मिला काम

जितेंद्र शर्मा • लखनऊ

'आपदा में अवसर...।' हौसला बढ़ाते इन तीन शब्दों को केंद्र और प्रदेश सरकार की नीति-प्रयासों का सहारा मिला तो उत्तर प्रदेश ने भी सफलता की नई इबारत लिख दी। सबसे अधिक आबादी और उसी अनुपात में चुनौतियों का बोझ सह रहे इस सूबे ने न सिर्फ कोरोना महामारी से छाए बेरोजगारी के बादलों को छांटा, बल्कि आत्मनिर्भरता में भी बड़ी छलांग लगाई है। सरकार के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि संक्रमण काल में 5.81 लाख नई इकाइयां खड़ी हो गईं, जिन्होंने 23.26 लाख लोगों को रोजगार दिया है।

पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के माध्यम से रोजगार देने वाले राज्यों की रैंकिंग जारी की थी। इसमें उत्तर प्रदेश ने शीर्ष पांच राज्यों में स्थान पाया है। कोरोना काल में दूसरे राज्यों से लौटे 40 लाख प्रवासी श्रमिकों और 23 करोड़ की आबादी की व्यवस्थाएं संभालने वाले यूपी का पांचवां स्थान काफी मायने रखता है। दरअसल, जब सभी राज्य संक्रमण काल से गुजर रहे थे, तब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज योजना से सहारा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता से अधिकारियों ने प्रदेश के हर एक जिले में पैकेज का लाभ देने के प्रयास शुरू किए।

एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.नवनीत सहगल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज की सहायता से प्रदेश में 5,81,671 नई इकाइयां शुरू हुईं। इसमें हर तरह की इकाइयां हैं, जिन्होंने कुल 23,26,684 लोगों को रोजगार दिया। 2,57,348 श्रमिक तो ऐसे हैं, जो पहले से चल रही इकाइयों में ही रोजगार पा गए। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से लौटे लगभग 40 लाख प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग अभियान चलाकर कराई गई। फिर उनके कौशल के मुताबिक रोजगार दिलाना शुरू हुआ। सिर्फ निर्माण इकाइयां जैसे रियल एस्टेट आदि के जरिये 1,14,466 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिल गया। इसमें सभी जिलों की सहभागिता रही। इन श्रमिकों को अब प्रदेश से पलायन कर नहीं जाना पड़ेगा।

योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

बड़ी उपलब्धि

- कोरोना को धता बता आत्मनिर्भरता में प्रदेश ने लगाई बड़ी छलांग
- रोजगार देने वाले राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश शीर्ष पांच में शामिल

आंकड़े एक नजर में

- वर्तमान में कार्यरत इकाइयां 8,07,537
- पहले से कार्यरत श्रमिक 48,13,401
- नए श्रमिक : 2,57,348
- निर्माण इकाइयों में लगे प्रवासी श्रमिक : 1,14,466
- नई इकाइयां : 5,81,671
- नई इकाइयों से सृजित रोजगार : 23,26,684

अक्टूबर में और तेजी से दौड़ी अर्थव्यवस्था

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लॉकडाउन से लड़खड़ायी अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने का जो सिलसिला जुलाई में शुरू हुआ था, उसने अक्टूबर के त्योहारी सीजन में और रफ्तार पकड़ी है। पिछले महीने अक्टूबर में सरकार को कुल 10,672 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो लक्ष्य का 86.9 फीसद है और पिछले साल के इसी माह की तुलना में 1828.44 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने 11,313.66 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 8844.35 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया था, जो लक्ष्य का 78.17 प्रतिशत था। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को बताया कि जीएसटी/वैट के जरिये सरकार ने अक्टूबर में 6951.52 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य तय किया था। इसके सापेक्ष अक्टूबर में इस मद में 5598.27 करोड़ रुपये मिले, जो लक्ष्य का 80.5 प्रतिशत है।

इसमें जीएसटी की हिस्सेदारी 3795.44 करोड़ रुपये और वैट की 1802.83 करोड़ रुपये है। खन्ना ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री में इजाफा होने से वैट का राजस्व बढ़ा है। आबकारी शुल्क के मद में अक्टूबर में लक्ष्य के सापेक्ष 106 फीसद कमाई हुई। अक्टूबर में 2250 करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जबकि आमदनी हुई 2403.02 करोड़ रुपये। संबंधित खबर » 8